ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

रविवारीय, 22-28 सितंबर 2019, वर्ष-एक, अंक-7,रांची | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN 00962 | कुल पृष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

पेजः 4 आरओ और वाटर प्यूरीफायर पर कितना भरोसा?

सूचना

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

झारखंड सरकार ने संथाल में बांस व जलकुंभी उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। संथाल परगना झारखंड के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है, लेकिन उस क्षेत्र में इस उद्योग को बढ़ावा देने के दुमका में आयोजित बांस मेला में सीएम ने अलग अलग क्षेत्रो में बैम्बू सुलभ केंद्र, चिरौंजी और ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट और कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन व शिलान्यास किया। ये सामाना अब इटली तक पहुंच रहा है।

टाना भगत देश के धरोहर हैंः मुख्य सचिव

रांची :मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने कहा कि टाना भगत समुदाय देश के ऐतिहासिक धरोहर हैं। टाना भगत विकास प्राधिकार का ध्येय इनका आर्थिक स्वावलंबन है। सरकार टाना भगतों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के उपायों पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टाना भगतों की जमीन से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करने के बाद सरकार अब उनके घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी आदि मूलभूत जरूरतों को भी लगभग पूरा कर चुकी है, जो भी थोड़े काम बचे हैं, उन्हें भी एक समयसीमा के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। उक्त बातें उन्होंने झारखण्ड मंत्रालय में टाना भगत विकास प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

हर बेटी को मिले सुकन्या का लाभ :मुख्यमंत्री

स्कूल में पढ़ाई कर रहीं सभी बच्चियों को सुकन्या योजना का लाभ दें कइससे बच्चियों को पढ़ाई में मदद मिलेगी, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में भी यह सहायक साबित होगा, बच्चियां अपने सपनों को पंख दे सकेंगी। आप सभी बच्चियां मन लगाकर पढ़ाई करें। ताकि अपने परिवार समाज, राज्य और देश का मान अपने कार्यों से बढ़ा सकें कये बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने अपने दुमका प्रवास के दौरान कुसुमडीह स्थित मिलेनियम स्कूल की बच्चियों से मुलाकात के क्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके सशक्तीकरण के लिए सरकार कार्य कर रही है।

सबसे बड़े तिरंगे को फहराने उतारने की कवायद के बाद पहाड़ी को हुये नुकसान पर नहीं है किसी की नजर

रांची पहाड़ी को बचाने के लिये ठोस कदम उठाने की जरूरत

रांची : राजधानी की पहचान और देश भर में अपने आश्चर्यजनक तथ्यों के कारण चर्चा में रहने वाला रांची पहाड़ी धीरे धीरे क्षरण की ओर है। हालांकि इसे बचाने औश्र इसके संरक्षण के लिये जब तब आवाजें उठती हैं, पर कोई ठोस कदम इसके लिये अब तक नहीं उठाया गया है। कुछ साल पहले तत्कालीन रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने देश के सबसे बड़े और ऊंचे तिरंगे को तो यहां फहरा दिया, पर यह पूरी कवायद पहाड़ी मंदिर के लिये खतरनाक साबित हुयी। तब पहाड़ी की भुरभुरी जमीन पर ऊंचा खंभा गाड़ दिया गया। इस प्रक्रिया में इसकी मिट्टी काटी गयी और इस पर जेसीबी चलाया गया। इससे अंततः पहाड़ी की जमीन के ही धंसने का खतरा बनता है। इसके अलावा पहाड़ी के एक तरफ अतिक्रमण की भी मार है। कुछ साल पहले यहां चारदिवारी देकर उस पर वृक्षारोपण किया गया था। और यह काम सफलतापूर्वक हुआ भी, पर पहाड़ी के समुचित संरक्षण के लिये अभी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

कभी पहाड़ी की पूरी भूमि पर घने वृक्ष हुआ करते थे जो इसे अपरदन से बचाते थे। रांची घूमने आने वाले ज्यादतर लोग पहाड़ी चढ कर पूरे रांची के मनोरम दृश्य को जरूर देखते थे। हाल के कुछ सालों में इसे सजाने संवारने के नाम पर ही इसे काफी नुकसान पहुंचाने का काम हुआ है।

पहाड़ी मंदिर, फांसी टुंगरी, रिची बुरू

अंग्रेज यहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देते थे इस कारण से इसका नाम फांसी टुगरी पड़ा। कुछ लोगों के अनुसार मुंडारी भाषा में इसका नाम रिची बुरू भी है। एतिहासिक तथ्य टटोलें तो यह पालकोट महाराजा का बगीचा हुआ करता था। शिव मंदिर बनने के बाद यह लोगों केआस्था का केंद्र बन गया। कुछ साल पहले चोटी पर स्थित शिवमंदिर को भव्य और विशाल बनाने की बात हुयी थी, पर जानकारों ने इस पर बड़े निर्माण को चातरनाक बताया, तो काम रोक दिया गया।

खोंडालाइट चट्टानों से बनी है रांची पहाड़ी

जाने माने जियोलॉजिस्ट नीतिश प्रियदर्शी बताते हैं कि जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो रांची पहाड़ी अब बूढा हो चुका है। यह खोंडालाइट चट्टानों से बना हुआ है और इसकी उम्र हिमालय से भी ज्यादा है। और इसकी मिट्टी बहुत ही उर्वर है। अब इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण इसके साथ ज्यादती होगी। इसके सीने पर भवन निर्माण करना इसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होगा। अब इससे अतिक्रमण हटा कर खूब पेड़ा पौधे लगा कर इसे बख्श देना चाहिये।

हर कदम पर मंदिर निर्माण

रांची पहाड़ी के शीर्ष पर शिव मंदिर है इन्हें लोग पहाड़ी बाबा भी कहते हैं। इसके अलावा पिछले तीन दशक में हर कुछ दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है। और आज भी कई मंदिरों का निर्माण इस किया जा रहा है। चुंकि पहाड़ी की मिट्टी इतनी मजबूत नहीं है कि बहुत सारे भवनों के निर्माण का बोझ उठा सके। इसके अलावा लोगों के सुविधा के लिये इस पर सीढियों की संख्या बढाने और उसमें रेलिंग लगाने, शेड बनाने का काम भी हुआ।

दूमका में आयोजित हुआ दो दिवसीय बांस कारीगर मेला

मेला का मुख्य उद्देश्य संथाल परगना के साथ साथ झारखंड के बांस कारीगरों को नई तकनीक से अवगत कराना

झारखंड के हस्तशिल्पकारों की कला अब विदेशों में आएगा नजर

10 बांस कारीगरों को वियतनाम और चीन भेजा जाएगा

सरकार उद्योग स्थापित करने में हर तरह से करेगी मदद :मुख्यमंत्री

दुमकाः. आउटडोर स्टेडियम दूमका में दो दिवसीय बांस कारीगर मेला का आयोजन किया गया। झारखंड के बांस से बनी सामग्री पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए यही सरकार का प्रयास है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में देश ही नहीं विदेशों के बाजार में भी झारखंड के हस्तशिल्पकारों के उत्पाद नजर आएंगे। हुनरमंद युवाओं और महिलाओं के अंदर छिपी कला को निखारना, अत्याधुनिक तकनीक से अवगत करा उनसे बेहतरीन उत्पाद का निर्माण करा उनकी कला को सम्मान व उनका मान बढ़ाना सरकार की मंशा है। इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने बांस कारीगर मेला में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी है कि झारखंड में निर्मित बांस के सामग्री की क्वालिटी पूरे देश में सबसे अच्छी है। झारखंड वनों से भरा प्रदेश है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वन है। यहां के युवाओं , महिलाओं को हुनरमंद बनाकर हम वन से उत्पादित उत्पाद को वैल्यू एडेड कर उनके आय को बढ़ा सकते हैं। मेला आयोजन का मुख्य उद्देश्य संथाल परगना के साथ साथ झारखंड के बांस कारीगरों को नई नई तकनीक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे बेहतर उत्पाद का निर्माण कर सके, जिसकी मांग पूरे विश्व में हो। सरकार लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है।

20 करोड़ बांस के पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, इंटीग्रेटेड बंबू पार्क की होगी स्थापना

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा 20 करोड़ बांस के पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 साल का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। संथाल परगना में अंतरराष्ट्रीय स्तरीय इंटीग्रेटेड बंबू पार्क की स्थापना की जाएगी ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के सामग्री का उत्पादन हो सके। मुख्यमंत्री ईयसएएफ कारखाना में बन रहे बांस के उत्पादों का अवलोकन किया।

रांची विवि में स्टूडेंड क्रियेटिविटी सेंटर भवन का राज्यपाल ने किया शिलान्यास

रांचीः शुक्रवार 20 सितंबर को पत्रकारिता विभाग के दो दशकों से बहुप्रतीक्षित भवन की नींव राज्यपाल ने मोराबादी कैंपस में रखी। विश्वविद्यालय के लीगल स्टडीज कैंपस के पास खाली भूखंड पर पत्रकारिता विभाग का भवन तैयार होगा।विभाग के लिये अपने भवन की पुरानी मांग थी। पद्मश्री बलबीर दत्त ,आर एन झा जैसे फाउंडर मेंबर के प्रयास से 1987 से चल रहे पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का आज तक अपना भवन नहीं है और यह आज भी पीजी आर्ट्स ब्लौक में पोलिटिकल साइंस के एक हिस्से में चलता है।विभाग के लिए भवन की मांग नये पुराने छात्र उठाते रहे थे, और झारखंड को पत्रकारों की दो पीढी देने वाले इस विभाग के खुद के भवन के लिये सभी प्रयासरत थे। इसे देखते हुये वीसी डॉ रमेश पांडेय, प्रोवीसी कामिनी कुमार, पत्रकारिता विभाग के वर्तमान निदेशक एवं रांची विश्वविद्यालय के वोकेशनल हेड डॉ अशोक कुमार चौधरी ने इसकी रूपरेखा तैयार की और राज्यपाल ने इसके निर्माण की नींव रखी गयी।वीसी डॉ रमेश कुमार पांडेय ने कहा कि, साढे तीन करोड़ की लागत से बनने वाला यह भवन तय समय में बन कर तैयार हो जायेगा।

सीसीएल में प्लास्टिक मुक्त भारत के लिये स्वच्छता रथ रवाना

रांचीः भारत सरकार की मुहिम 'स्वच्छता ही सेवा' के अंतर्गत आज सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस परिसर, रांची में सीसीएल के सीएमडी श्री गोपाल सिंह, निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री वी.के. श्रीवास्तव तथा निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री भोला सिंह ने '' एक कदम प्लास्टिक वेस्ट मुक्त भारत की ओर'' संदेश के साथ ''स्वच्छता रथ'' को हरि झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ रांची के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के दुष्प्रभाव से आमजन को जानकारी देगा साथ ही जागरूक करेगा और स्वच्छता के संदेश का प्रचार-प्रसार करेगा। अवसर विशेष पर दरभंगा हाउस परिसर में झारखंड फिल्म और थिएटर अकादमी द्वारा एक 'नुक्कड़ नाटक' का आयोजन किया गया, जिसमें कालाकारों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के विभिन्न नकारात्मक पहूलओं पर रोचक ढंग से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर सीएमडी श्री गोपाल

सिंह ने कहा कि आपने नाटक के माध्यम से जो स्वच्छता का संदेश दिया है उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। गोपाल सिंह ने कलाकारों को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित भी किया। सीसीएल के सीएसआर विभाग ने विभिन्न तरीकों से प्लास्टिक को कार्यस्थल में कैसे कमी आये, इससे संबंधित पोस्टर तैयार किया है। सीसीएल मुख्यालय प्रागंन में प्रदर्शित किया जायेगा। सीएमडी एवं निदेशकगण ने जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वच्छता पोस्टर का विमोचन भी किया।

निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री वी.के. श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छता शुरूआत स्वंय से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करनी होगी। सीसीएल द्वारा ''एक कदम प्लास्टिक वेस्ट मुक्त भारत की ओर'' के संदेश के साथ सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 11 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2019 तक ''स्वच्छता ही सेवा'' सीएमडी, सीसीएल गोपाल सिंह के मार्गदर्शन में मनाया जा रहा है।

बालाजी डेंटल केयर

आरसीटी सहित समस्त दंत रोगों की चिकित्सा उपलब्ध।

Address: Shiv Bhawan, Laah Kothi, Ratu Road, Ranchi-5
Ph. 9006833759

झारखंड की नदियों के अस्तित्व पर खतरा

डॉ. नीतिश प्रियदर्शी

आज नदियों अस्तित्व ही खतरे में है। सब जानते हैं कि नदियों के किनारे ही अनेक मानव सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। नदी तमाम मानव संस्कृतियों की जननी है। प्रकृति की गोद में रहने वाले हमारे पुरखे नदी-जल की अहमियत समझते थे। निश्चित ही यही कारण रहा होगा कि उन्होंने नदियों की महिमा में ग्रंथों तक की रचना कर दी और अनेक ग्रंथों-पुराणों में नदियों की महिमा का बखान कर दिया। भारत के महान पूर्वजों ने नदियों को अपनी मां और देवी स्वरूपा बताया है। नदियों के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, इस सत्य को वे भली-भांति जानते थे। इसीलिए उन्होंने कई त्योहारों और मेलों की रचना ऐसी की है कि समय-समय पर समस्त भारतवासी नदी के महत्व को समझ सकें। नदियों से खुद को जोड़ सकें। नदियों के संरक्षण के लिए चिंतन कर सकें। अगर नदियां ही नहीं रहेंगी तो मानव सभ्यता ही खतरे में पद जाएगी। झारखण्ड में भी नदियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। नदियों का महत्व जानना हो तो इसके इतिहास को भी जानना

होगा की कैसे और कब झारखण्ड में नदियां अस्तित्व में आईं। नदियों का जन्म एवं विकास एक लम्बी कहानी है। हर नदियों का अपना एक उद्गम स्थल होता है। नदी का उद्गम पहाड़, जंगल आदि क्षेत्र में होता है। इनका जन्म यकायक नहीं होता, प्रत्युत्त क्रमबद्ध विधि से अनेक जलधाराएं मिलकर एक पूर्ण विकसित सरिता का रूप लेती है। नदियों की उत्पत्ति कब हुई ये कहना बहुत मुश्किल है लेकिन संभावना व्यक्त की जा सकती है। अगर छोटानागपुर पठार की बात करे तो ये प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। यहाँ के चट्टानों की आयु ६०० मिलियन वर्ष से भी अधिक है । तो यहाँ की नदियां भी करोडो साल पुरानी होंगी। गंगा यमुना से भी बहुत पुरानी। हिमालय बनने के बाद गंगा, यमुना इत्यादि नदियां अस्तित्व में आईं। झारखंड के पठार हिमालय से भी करोड़ों साल पुराने हैं। हिमालय की उत्पत्ति आज से लगभग ५० से ६० मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई जब भारतीय प्रायद्वीप तिब्बत के पठार से टकराया।

जब हिमालय बन रहा था उसी वक़्त झारखण्ड में भी काफी उथलपुथल हो रहा था। वैसे हिमालये बनने के करोड़ों साल पहले भी यहाँ उथल पुथल हुआ था जिसका साक्ष्य यहाँ के चट्टानों में पड़े वलन से पता चलता है। आज से लगभग ४०० मिलियन वर्ष पहले डेवोनियन काल में झारखण्ड में दामोदर घाटी का निर्माण हुआ जहाँ से होके दामोदर नदी बहती है। इस काल को मत्स्य काल भी कहते हैं। उस वक़्त पृथ्वी पर विशाल पर्वत बनने की प्रक्रिया चल रही थी। चट्टानों में लम्बी दरारें पड़ी जो शायद आगे चल के नदियों के उद्गम में प्रमुख भूमिका निभाया।

आज जो हम रांची के पठार की बनावट देख रहे हैं करोडो साल पहले ऐसी नहीं थी। ये एक बेसिन था जो बाद में सडीमेंट्स या अवसाद से भर गया तथा बाद में एक पठार का रूप लिए और उसके बाद शायद स्वर्णरेखा, कोयल, कारो इत्यादि नदियों की उत्पत्ति हुई होगी। हिमालय बनने के दौरान यहाँ ज्यादा ही उथल पुथल हुआ। घाटियाँ बनी , कुछ भाग उठा तो कुछ भाग धंसा, जल प्रपात बने । छोटानागपुर की पठार की नदियां या तो पहाड़ से निकली जैसे दामोदर या फिर धरती के नीचे से जैसे सवर्णरेखा।

झारखंड में चलेगा श्रमशक्ति अभियान

रांचीः पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक राज्य सरकार पूरे राज्य में श्रमशक्ति अभियान चलाने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को निबंधित कर उनके लिए बनी केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ दिलाना है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने इसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताते हुए कहा कि हमें गांव व शहरों से लेकर लातेहार के सरयू और लोहरदगा के पेशरार जैसे सुदूर दुर्गम स्थानों के मजदूरों को भी इससे जोड़ना है। इसके लिए प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा असंगठित क्षेत्र के एक-एक कामगार को जागरूक कर उनका हक दिलाना है।

इसी मकसद से झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित तमाम जिला तथा प्रखंड समन्वयकों सहित श्रम प्रसार पदाधिकारियों और श्रमाधीक्षकों के साथ बैठक कर उन्होंने शत प्रतिशत मजदूरों के निबंधन पर बल दिया। मुख्यमंत्री 25 सितंबर को अभियान की शुरुआत करेंगे ।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty
info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

विकास के नाम पर जंगलों की बलि

पलामू में मंडल डैम के निर्माण में तकरीबन साढे तरन लाख पेड़ काटे जायेंगे। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। इन साढे तीन लाख पेड़ो में ज्यादतर वो विशाल वृक्ष हैं तो दशको पुराने हैं और इनकी कटाई से पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। पर्यावरणविदों ने इसको लेकर चिंता व्यक्त की गयी है। मंडल डैम को निर्माण 1970 में हीं प्रारंभ किया गया था और 1980 तक में बहुत सारे पेड़ काट डाले गये थे। उसके बाद जनविरोध के कारण काम रोक दिया था। तब से लेकर आज तक में वहां के जंगल काफी घने और विशाल वृक्षों वाले हो गये हैं। अब फिर से डैम के निर्माण को मंजूरी दी गयी है और इसके लिये अक्टूबर से जंगलों की कटाई होगी। इससे 1007 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि से जंगल खत्म हो जायेंगे। इसके बाद भी जंगलों पर से खतरा टला नहीं है। जानकारों का कहना है कि, जलाशय के निर्माण के बाद भी इस बात की आशंका है कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जायेगा। सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिये यह डैम आवश्यक है। मंडल डैम के शुरू होने के बाद डालटनगंज और पलामू क्षेत्रों में कुछ लाख हेक्टेयर जमीन और बिहार के कुछ जिलों में खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। बताया जाता है कि परियोजना पर 800 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। 2007 में, पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी के अभाव और बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्रों के डूबने की आशंका से इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया था। इस वर्ष के प्रारंभ में राज्य सरकार ने इस परियोजना को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। अभी जो पेड़ काटे जायेंगे वो साल के वृक्ष हैं। वैज्ञानिक तौर पर ये साबित हो चुका है कि जहां साल के वृक्ष होते हैं वहां जलस्तर भी ठिक रहता है। इन जंगलों की कटाई की भरपाई के लिये इतने ही पेड़ पलामू बाघ परियोजना में लगाने की बात कही गयी है। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। क्या उतने पेड़ जिम्मेवारी के साथ वहां लगाये जायेंगे? उनका संरक्षण होगा? और सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि, कौन से पेड़ लगाये जायेंगे? पेड़ लगाने के नाम पर महज खानापुर्ति तो नहीं होगी?

मंडल डैम के निर्माण में साढे तीन लाख पेड़ काटे जायेंगे। विकास के लिये पेड़ों का कटना कोई गलत कदम नहीं। कानूनी प्रावधान है कि जितने पेड़ किसी निर्माण के दरम्यान काटे जायेंगे उससे ज्यादा लगाये भी जायेंगे। लेकिन इसका पूरी तरह से पालन कौन करता है? कोई इसे जिम्मेवारी से मोनिटर करने वाला भी नहीं होता। हश्र ये होता है कि, वर्षों में तैयार हुये जंगल निर्माण के नाम पर घंटो में काट दिये जाते हैं, पर वापस उतने जंगल लगे, उनका संरक्षण हुआ या नहीं या सिर्फ खानापुर्ति कर ली गयी ?यह सब सुनिश्चित नहीं हो पाता है।

ठिक ऐसी ही स्थिति मुंबई के आड़े क्षेत्र का भी है। आड़े का इलाका महानगर में होते हुये भी बहुत हीं घने बाग बगीचों वाला है अब यहां से जंगलों का सफाया कर वाहनों के लिये पार्किंग बनाया जायेगा।महाराष्ट्र सरकार के इस प्लान का वहां मनसे सहित पर्यावरणविदों ने विरोध किया है। वहीं सरकार की दलील है कि आड़े से जंगलों का सफाया कर वाहनों को यहां रखने से मुंबई की ट्रैफिक को राहत मिलेगी। पहले भी देश के कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि निर्माण और विकास के नाम पर पर्यावरण एवं कृषि योग्य भूमि को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और बाद में उस काम से भी हाथ खीच लिया गया। बंगाल में सिंगुर इसका उदाहरण है जहां कार की फैक्ट्री लगाने के लिये कृषि योग्य भूमि को लिया गया और वहां कुछ निर्माण हुआ उसके बाद राजनितिक एवं किसानों के विरोध के कारण प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। इससे वहां अच्छी खासी कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो गयी थी। कुछ ऐसा ही हश्र बहुत पहले महाराष्ट्र में कुछेक पावर प्लांट बनाने के लिये लिये गये भूमि का भी हुआ था।

हमें विकास के लिये पर्यावरण के साथ समझौता करना पड़ सकता है। कई देशों में पहले बंजर या पथरीली भूमि को ही चुनने को प्रावधान है। आवश्कतायें ऐसी हो सकती हैं कि हमें किसी हरियाली को खत्म करना पड़े, लेकिन उसके लिये ईमानदारी से भरपाई का काम भी ठोस रूप में करना आवश्यक है।

जीन संवर्द्धित बीजों पर मौजूदा नीति की समीक्षा का वक्त

सुरिंदर सूद

जीएम बीज यानि जिनेटिकली मोडिफाईड वैसे बीज जिन्हें कृत्रिम तौर पर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा बनाया है जो प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छी फसल देते हैं, कीटों और खराब मौसम का इन पर प्रभाव नहीं होता। इस–ाके विरोधियों का मानना है कि इन बीजों में वालवर्म जैसे हानिकारक बैक्ट्रिया होते हैं जो मनुष्यों और मवेशियों के पेट में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन इसके उपयोग और रोक पर बहस जारी है

आनुवांशिक रूप से संवर्द्धित (जीएम) जीन के खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरण क्षेत्र में पहुंच जाने के बारे में अगर कोई संदेह था तो बैगन, सरसों और कपास जैसी फसलों के गैर-अनुमोदित जीएम बीजों की बड़े पैमाने पर खेती होने की जानकारी सामने आने के साथ ही उसे दरकिनार कर देना चाहिए। असल में, यह जीन संरचना में छेड़छाड़ कर विकसित पहली फसल बीटी-कॉटन के पहले ही हो जाना चाहिए था। बीटी कॉटन में बैसिलस थुरिन्जींसिस (बीटी) बैक्टीरिया से निकला हुआ एक विदेशी जहरीला जीन भी मौजूद था।

कृषि क्षेत्र में कीटनाशक बीटी जीन का इस्तेमाल असल में आनुवांशिक रूप से संवर्द्धित फसलों के विकास के पहले ही शुरू हो गया था। दुनिया भर में किसान दशकों से बीटी बैक्टीरिया का इस्तेमाल सूक्ष्मजीवी कीटनाशक एजेंट के तौर पर करते रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती में भी यह एक आम बात मानी जाती है। इसके अलावा मिट्टी में पाया जाने वाला आम बैक्टीरिया बीटी गलती से पशुओं एवं इंसानों के पेट में भी पहुंच जाता है। माना जाता है कि आयात किए जाने वाले कई खाद्य पदार्थों में किसी तरह की घोषणा के बगैर भी जीएम तत्त्व मौजूद होते हैं। इस तरह बीटी बीज की तुलना लोककथा के मशहूर किरदार जिनी से करने वाले जीएम-विरोधी एक्टिविस्ट पहले से ही सक्रिय हैं। अगर इसे स्वास्थ्य, पर्यावरण या जैव-विविधता को कोई चोट पहुंचानी होती तो वह अब तक कर चुका होता। लेकिन इस तरह का सुलभ साक्ष्य शायद ही मौजूद है। ऐसे में नए जीएम बीजों को मंजूरी देने पर लगी रोक जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। आनुवांशिक रूप से संवर्द्धित बीजों को मिलने वाला किसानों का समर्थन एक तरह से आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक की ही वकालत करता है। किसान जानबूझकर कानून का उल्लंघन करते हुए गैर-अनुमोदित जीएम फसलों को लगा रहे हैं जो एक तरह से उनके 'सविनय अवज्ञा' आंदोलन की ही तसदीक करता है। सरकारी अनुमोदन न होने के बावजूद जिस तरह से जीएम बीजों की मांग बढ़ी है उसने इन बीजों की आपूर्ति शृंखला को भी जन्म दिया है। यह जीन में बदलाव कर विकसित की गई नई फसलों के प्रति किसानों के बढ़ते लगाव का भी सबूत देता है। जीएम-समर्थक किसानों का मानना है कि उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और कृषि को व्यवहार्य बनाने के लिए ऐसे बीजों की मौजूदगी जरूरी है।महाराष्ट्र के अकोला में किसानों ने अनधिकृत कपास की एचटीबीटी किस्म वाले बीज को पहली बार अपने खेतों में लगाया था। वहां से शुरू हुआ उनका प्रतिरोध धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी फैल चुका है और अब इस सूची में आनुवांशिक रूप से संवर्द्धित बैगन एवं सरसों की फसलें भी शामिल हो चुकी हैं। बिना मंजूरी वाले जीएम बीज बेचने वाले दुकानदारों और ऐसी फसलें उगाने वाले किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने, खेतों में तैयार हो चुकी फसल को बरबाद कर देना और संदिग्ध बीजों को जब्त करने जैसे दंडात्मक कदम भी किसानों को डिगा नहीं पाए हैं। किसान अपने इस प्रतिरोध को 'सत्याग्रह' का नाम देकर विरोध जताने के महात्मा गांधी के इस अहिंसक तरीके को नई ऊर्जा दे रहे हैं। सरकार ने हाल ही में लोकसभा में यह स्वीकार किया था कि अनुमोदन नहीं मिलने के बावजूद एचटीबीटी-कपास की फसल महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बोई जा रही है। कृषि मंत्रालय की खेत निरीक्षण एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन समिति का अनुमान है कि वर्ष 2017-18 में कपास के कुल रकबे में से करीब 15 फीसदी इलाके में एचटीबीटी किस्म ही बोई गई थी। कपास और अन्य फसलों के जीएम बीजों की आपूर्ति के नियमित चैनल अब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी व्यवस्थित ढंग से पाए जाते हैं। इस तरह जीएम तकनीक के विरोधियों के दबाव में आकर सरकार का किसानों के इस पसंदीदा बीज किस्म पर रोक लगाने का कदम सही दिशा में जाता नहीं दिख रहा है। सरकार को अपनी इस नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। भले ही किसानों के जीएम सत्याग्रह का सामना कर रही राज्य सरकारों ने किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने के संकेत दिए हैं लेकिन केवल इतने भर से बात नहीं बनेगी। सरकार को जीएम बीजों के बारे में अपनी समग्र नीति पर ही नए सिरे से गौर करने की जरूरत है। इसके बारे में अनिश्चितता कायम रहने से जीन-संवर्द्धन तकनीक से संबंधित शोध पर गहरा आघात लगा है और इसकी वजह से जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों में विदेशी निवेश की आवक भी प्रभावित हुई है। जीएम फसलों का विरोध करने वाली लॉबी काफी मुखर है लेकिन सरकार को इन लोगों के दुष्प्रचार के आगे कदम न टेकते हुए वैज्ञानिकों, संस्थानों और शोध केंद्रों की समझ भरी सलाह पर गौर करना चाहिए। जीएम उत्पादों के सुरक्षा संबंधी पहलुओं को नियंत्रित परिवेश एवं खुले खेतों में कठोर परीक्षण के जरिये परख लिए जाने के बाद इनके व्यावसायिक इस्तेमाल पर मंजूरी रोकने के पीछे कोई भी कारण नहीं रह जाता है। सरकार को जीन में बदलाव करने वाले इस तकनीक से होने वाले फायदों की तारीफ करने की जरूरत है।भारतीय परिवेश के लिहाज से उसके अनुकूलन का आकलन करने के बाद ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर भारतीय कृषि भी तकनीक आधारित क्षेत्रों की तरह पिछड़ी ही रह जाएगी।

अब बाढ सिर्फ ग्रामीण इलाकों को ही प्रभावित नही करती। पर्यावरण असंतुलन के कारण बाढ की समस्या से मुंबई और चेन्नई महानगर भी त्रस्त होते हैं

पर्यावरण असंतुलन का परिणाम है बाढ़

डॉ नारायण मूर्ति

क्या कारण है कि जब हम ये मान कर चल रहे हैं कि इस वर्ष अब मॉनसून समाप्त है। लेकिन इसके आखिरी समय में भी कुछ जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी है

देश के पूर्वोत्तर इलाके में असम, पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण में केरल और कर्नाटक-ये सभी ऐसे राज्य हैं, जो हाल के वर्षों में बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश की चपेट में आए हैं। नतीजतन गुजरात के वड़ोदरा, अहमदाबाद, संपूर्ण केरल और कर्नाटक के कूर्ग, बेलगावी शहरों में अभूतपूर्व बाढ़ आ गई। बारिश से फसलें, मवेशी, वन्यजीव, आधारभूत ढांचे, कृषि एवं अर्थव्यवस्था-सभी प्रभावित हुए हैं। अर्थव्यवस्था पर बाढ़ के प्रभाव के आंकड़े अलग-अलग हैं, लेकिन यदि विश्लेषण किया जाए, तो नुकसान का आंकड़ा आसानी से जीडीपी के 0.25 फीसदी तक पहुंच सकता है। बाढ़ के आर्थिक प्रभाव का पहला संकेत तब मिलता है, जब लोग कम खर्च करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका प्रभावित होती है, जिससे खर्च करने के लिए उनके पास कम पैसे होते हैं। शहर-गांव एक समान-प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती। मसलन, ज्यादातर लोग समझते हैं कि भारी बारिश का असर केवल ग्रामीण इलाकों में ही महसूस किया जाता है। ऐसा निश्चित रूप से होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शहरों में बड़ा असर देखने को मिला है। व्यावसायिक राजधानी मुंबई ने 2006 के प्रलय के बाद से भारी बारिश का सामना किया है, जिससे शहर के डूबने की आशंका पैदा हो गई।हर वर्ष मुंबई कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का सामना करती है, जब हवाई अड्डे को बारिश के चलते पूर्णत या आंशिक रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के मामले में, उद्योगों या उन केंद्रों से खरीदे जाने वाले कच्चे माल पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। 2018 में केरल की बाढ़ में रबर और नारियल उत्पादन, दोनों प्रभावित हुए जिसका रबर और नारियल तेल आधारित उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनियों पर असर पड़ा। स्थानीय अर्थव्यवस्था बाढ़ से सबसे ज्यादा बाधित होती है। वैसे राज्य, जहां की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वे बाढ़ के कारण ज्यादा प्रभावित होते हैं। बिहार और असम के ऊपरी इलाके में लगातार बाढ़ वहां किसी भी तरह की औद्योगिक गतिविधियां न होने का प्रमुख कारण है।आजीविका की लागत- घर, वाहन और घरेलू सामान की क्षति ऐसे प्रत्यक्ष नुकसान हैं, जिनका सामना बाढ़ प्रभावितों को करना पड़ता है। अपने देश में आधारभूत ढांचे की बदहाली को देखते हुए कहा जा सकता है कि सार्वजनिक उपयोग के निर्माणों, जैसे पुलों, रेलवे लाइनों, सड़कों, स्कूलों और हाउसिंग सोसाइटियों को नुकसान पहुंचा है। जरा उन छोटे उद्यमियों की दुर्दशा की कल्पना कीजिए, जिन्हें घर और व्यवसाय के नुकसान की दोहरी मार झेलनी पड़ी है। मसलन, एक छोटे दुकानदार की दुकान का सामान नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी दुकान अपने घर में होती है। उसके आपूर्तिकर्ता को भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ता है, जिससे उधार लेने में समस्या पैदा होती है और उसे या तो अपने व्यवसाय का स्तर कम करना पड़ता है या कई मामलों में बंद करना पड़ता है। आपदा प्रबंधन बेहतर होने की वजह से हाल के दौर में जानमाल का नुकसान कम हुआ है, लेकिन आर्थिक नुकसान कम होने के कोई संकेत नहीं हैं। इसके विपरीत हर बाढ़ के बाद राज्य का आर्थिक बोझ बढ़ ही जाता है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों से बाढ़ से होने वाले नुकसान की खबरें आ रही हैं, क्योंकि खराब जल निकासी और खराब बुनियादी ढांचे के कारण बाढ़ आई। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के एक हिस्से के रूप में, बाढ़ के कारण 2011 के बाद नुकसान उत्तर-पूर्वी राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और मेघालय और उत्तर में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है।फिर बारिश और बाढ़ के चलते दावों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी के कारण बीमा कंपनियों ने नुकसान की बात कही है। बाढ़ के आर्थिक प्रभाव पर वापस लौटें, तो मान लीजिए कि औसत उद्यमी दो परिवारों को चलाता है, तो बारिश के कारण इन परिवारों पर प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में अधिक उद्यमी, अनियोजित क्षेत्र में काम करने वाले लोग और छोटे व्यवसायी हैं। बाढ़ से उनका जीवन तो प्रभावित होता ही है, अर्थव्यवस्था में उनके द्वारा किया जाने वाला योगदान भी बाधित होता है।वर्ष 2015 के वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अध्ययन से पता चला था कि शहरों का विस्तार और जलवायु चुनौतियों के भीषण होने से भारत में बाढ़ से संबंधित जोखिम काफी बढ़ सकते हैं। ये जोखिम खराब बुनियादी ढांचे के साथ बाढ़ प्रभावित शहरों में बढ़ जाते हैं, जहां नालियां पानी की मात्रा या धार को संभालने के लिए सक्षम नहीं हैं। वास्तव में जैसे-जैसे विद्युतीकरण का विस्तार हो रहा है, बारिश या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान भी बढ़ रहा है।बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन को सुचारू ढंग से चलाने की हमारी क्षमता धीमी है। बिजली की खपत आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाती है, जो बिजली की खराबी से बाधित होती है। बिजली उत्पादन कम होने से खेती, उद्योग, घरेलू खपत आदि सभी बुरी तरह प्रभावित होती हैं। इस प्रकार उत्पादन कम हो जाता है, जो अर्थव्यवस्था में परिलक्षित होता है।जलवायु परिवर्तन के साथ भारी और अचानक मूसलाधार बारिश एक वास्तविकता है, इसकी लागत जब जोड़ी जाती है, तो वही काफी ज्यादा होती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ नुकसान को कम किया जा सकता है, लेकिन आर्थिक नुकसान वास्तविक है, जो हर बीतते वर्ष के साथ बढ़ता जा रहा है।

गुमला में सिंगल यूज प्लास्टिक सरकारी कार्यालयों में बैन

गुमला :उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी शशि रंजन ने पत्र जारी कर जिले के सभी जिला स्तरीय तकनीकि एवं गैर तकनीकि पदाधिकारी, जिला अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला, बसिया, चैनपुर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित जिले के सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी प्रतिष्ठानों व कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बन्द करने के निर्देशानुसार आप अपने अधीनस्थ सभी प्रतिष्ठानों एवं कार्यलयों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बन्द करते हुए ऐसे सभी सामग्रियों के उपयोग पर पूर्णतः एवं सख्ती से रोक लगाएं।साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन को जिले में सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भा0प्र0से0, सहायक समाहर्त्ता सह सहायक जिला दण्डाधिकारी गुमला श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया है। इस जांच दल के जांच के दौरान आपके प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पाए जाने पर आपके विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी अंकित करते हुए सरकार को प्रतिवेदित किया जाएगा।

पीपल् बरगद नीम का वृक्षारोपण है जरूरी

जल स्तर लगातार कम होने का कारण आपने कभी जानने का कोशिश किया है, प्रत्येक वर्ष गर्मी जी का जंजाल बनती जा रही है आखिर क्यों?पिछले 68 सालों में पीपल, बरगद, और नीम के पेडों को सरकारी स्तर पर लगाना बन्द किया गया है। पीपल कार्बनडाई ऑक्साइडका 100% बरगद 80% और नीम 75 % एबजार्बर है । अब सरकार ने इन पेड़ों से दूरी बना ली तथा इसके बदले विदेशी यूकेलिप्टस को लगाना शुरू कर दिया जो जमीन को जल विहीन कर देता है । ऐसे में गर्मी तो बढ़ेगी ही और जब गर्मी बढ़ेगी तो जल भाप बनकर उड़ेगा ही । हर 500 मीटर की दूरी पर एक पीपल का पेड़ लगाये तो आने वाले कुछ साल भर बाद प्रदूषण मुक्त हिन्दुस्तान होगा। पीपल के पत्ते का फलक अधिक और डंठल पतला होता है जिसकी वजह शांत मौसम में भी पत्ते हिलते रहते हैं और स्वच्छ ऑक्सीजन देते रहते हैं।पीपल को वृक्षों का राजा कहते है।

ब्राजील के राष्ट्रपति बोलनसारो को अपने ही देश में लगी इस आग से कोई परेशानी नहीं, वो जंगलो को नष्ट कर उद्योग लगाना चाहते हैं5

चिंतन अमेजन की आग सिर्फ दुर्घटना नहीं

- अमेजन का अपना एक ईकोसिस्टम था। यह जंगल अपना खुद का बादल बनाता था।
- ब्राजील के अलावा बोलिविया पेरू के जंगलों में भी आग ने तांडव मचाया वहां भी भारी नुकसान हुआ है।

तमाम दुनिया में आज के दिन अमेजन को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। लोग अलग-अलग हैशटैग के जरिए इसे ट्वीट कर रहे हैं। सबके सामने अमेजन की चिंता है। आखिर, अमेजन में हो क्या रहा है?

अमेजन कभी एक घना जंगल हुआ करता था। यहां पर गगनचुंबी पेड़ों के चंदोवे धरती को इस तरह से ढंक लिया करते थे कि जमीन पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। इस विशाल जंगल में हजारों जलधाराएं बहा करती थीं। इस विशालकाय जंगल का अपना एक ईकोसिस्टम था। यह जंगल अपना खुद का बादल बनाता था और अपनी खुद की बारिशें भी पैदा कर लेता था। लेकिन, समय के साथ यह जंगल लगातार सिकुड़ता जा रहा है।माना जाता है कि धरती पर 20 फीसदी ऑक्सीजन अमेजन के जंगल पैदा करते हैं। माना जाता है कि धरती पर 20 फीसदी ऑक्सीजन अमेजन के जंगल पैदा करते हैं। ब्राजील में बोलसोनारो के सत्ता में आने के बाद से तो इसमें ऐसी तेजी आई है कि लग रहा है कि बस अब इसका खात्मा होने में कुछ ही समय बाकी है। यहां पर हर मिनट तीन फुटबॉल के मैदान जितना जंगल साफ किया जा रहा है। जब ब्राजील की स्पेस एजेंसी ने इसका खुलासा किया तो पहले तो बोलसोनारो ने डाटा को गलत बताया। लेकिन, स्पेस एजेंसी के प्रमुख अपने डाटा पर अड़े रहे तो बोलसोनारो ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। माना जाता है कि धरती पर 20 फीसदी ऑक्सीजन अमेजन के जंगल पैदा करते हैं। यहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का चालीस फीसदी हिस्सा मौजूद है। लेकिन, अब इस पूरे जंगल को साफ करके यहां पर मीट इंडस्ट्री व अन्य माल कमाऊ उद्योग खड़ा करने की योजना है। केन्द्र में सिर्फ और सिर्फ मुनाफा है। ऐसा जंगल किस काम का, जो कॉरपोरेट को मुनाफा भी न दे सके। जंगल साफ करके यहां पर जगह-जगह आग लगा दी गई है। ताकि, जमीन पूरी तरह से साफ हो जाए। इसके चलते इतना ज्यादा धुआं उठ रहा है कि उस धुएं को अंतरिक्ष से भी देखा जा रहा है। आसपास के शहरों में इसका धुआं फैल गया है और दिन में भी अंधेरे जैसी स्थिति बनती जा रही है। पिछले साल की तुलना में आग लगने की घटनाओं में 80 फीसदी का इजाफा हुआ है। अमेजन की

इस आग की चपेट में तमाम जीव-जंतु झुलसकर कोयला हो गए हैं। कभी कार्बन सोखकर ऑक्सीजन पैदा करने वाला अमेजन अब ऑक्सीजन सोखकर कार्बन पैदा कर रहा है। इस पर भी शायद कोई कहे कि हमें क्या? अमेजन हमारे लिए सांस ले रहा है। धरती के फेफड़े वहां पर मौजूद थे। अब इन फेफड़ों में दमघोंटने वाला धुआं घुस गया है।

आदिवासी महिलाओं के लिये हम सबमिलकर विकास के लिए समाजहित में कार्य करें:मुख्यमंत्री

पाकुड़: आप अपने हिस्से की जिम्मेवारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव से करें। रोशनी सखी मंडल ग्रुप की बहनों को बधाई। यह जानकर अच्छा लगा कि कपड़े का बैग बनाकर आप आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सरकार द्वारा आपके सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा कार्य अब नजर आ रहा है। 2014 तक राज्य में मात्र 43 हजार सखी मंडल का गठन हुआ था अब 2019 में यह बढ़कर करीब 2 लाख 17 से अधिक हो गया है। 28 लाख से अधिक आप बहने इससे जुड़ी हुई हैं। यह सब आपको स्वरोजगार से जोड़ने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के उ-द्देश्य से ही हमने यह किया है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने पाकुड़ परिसदन में सखी मंडल की महिलाओं से मुलाकात के दौरान कही।

संथालपरगना के लोग सालों से गुमराह हुए, अब विकास हुआ...

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने स्वार्थवश संथालपरगना की महिलाओं और पुरुषों को गुमराह कर इस क्षेत्र को विकास में पीछे छोड़ दिया। अब यह युग विकास का युग है, आप गुमराह हुए जन जन तक जाकर सरकार की विकासपरक मंशा, नीति और नीयत की जानकारी दें। जब गांव का एक एक व्यक्ति जागेगा और विकास का महत्व समझेगा तभी देश, राज्य, समाज और परिवार का विकास व आर्थिक उन्नयन संभव होगा। इसलिए अपने हिस्से की जिम्मेवारी का निर्वहन हम सभी को करना चाहिए।

सीसीएल को बेस्ट इन क्लास अवार्ड

बैंगलोर में आयोजित 17 सितम्बर को एशिया पैसिफिक एचआरएम, कांग्रेस में ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में सीसीएल को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए "बेस्ट इन क्लास" अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीसीएल की ओर से, श्री उमेश सिंह, जीएम (पी एंड आईआर) और श्री मनिष कुजूर, सहायक प्रबंधक (कार्मिक), श्री अभिलाष सिंह, उप प्रबंधक (कार्मिक) ने पुरस्कार प्राप्त किया।

17 से 21अक्टूबर 2019 तक मोरहाबादी मैदान में दिवाली मेला का आयोजन किया जाएगा

- महिलाओं को प्लेटफार्म प्रदान करना जेसोवा का उद्देश्य
- राज्य के बांस कारीगर अपने उत्पाद का कर सकेंगे ब्रांडिंग
- मेले में रहेगा पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था पर जोर
- समाज का सर्वांगीण विकास जेसोवा का ध्येय

मनु झा
सचिव, जेसोवा

रांची: झारखण्ड आई.ए.एस.ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (जेसोवा) की सचिव श्रीमती मनु झा ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो यह जेसोवा का मूल उद्देश्य है. छोटे-छोटे उद्योगों से जुड़ी महिलाओं को जेसोवा दिवाली मेला 2019 मंच प्रदान कर रहा है. जेसोवा का दिवाली मेला आगामी 17 से 21 अक्टूबर तक रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगी. इस मेले में राज्य के सभी जिलों से महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्टॉल लगा रही हैं. मेले के माध्यम से रोजगार के साथ-साथ उनके द्वारा निर्मित उत्पाद का ब्रांडिंग भी हो सकेगा. उन्होंने कहा कि इस वर्ष जेसोवा दिवाली मेले में बांस आधारित उत्पाद का भी स्टॉल लगाया जा रहा है. बांस आधारित उत्पाद का बाजार में भारी मांग है जिस-ाको देखते हुए झारखंड के बांस कारीगरों को विशेष तौर पर मेले में सहभागी बनाया गया है. उक्त बातें जेसोवा की सचिव श्रीमती मनु झा ने बूटी रोड स्थित आईएस क्लब में प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं।

संथाल परगना से भी पहुंचेंगे बांस कारीगर

श्रीमति मनु झा ने बताया कि इस वर्ष जेसोवा दिवाली मेले में विशेष तौर पर राज्य के संथाल परगना प्रमंडल के कई बांस कारीगरों को स्टॉल दिया गया है जिसके माध्यम से बांस कारीगर अपने हुनर के माध्यम से बांस आधारित उत्पाद लोगों को बेच सकेंगे. इसी प्र-कार राज्य के सभी जिलों से महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने समूह द्वारा निर्मित प्रोडक्ट भी मेले में बेच सकेंगे. उन्होंने बताया कि झारखंड के कारीगरों को मेले में विशेष तौर पर मौका मिलेगा जिससे वह अपने उत्पाद का ब्रांडिंग और बिक्री कर पाएंगे।

सिल्क कारीगरों को मिलेगा मौका

इस बार मेले में सिल्क कारीगरों को भी अपने उत्पाद का ब्रांडिंग करने का अच्छा मौका मिलेगा. सिल्क क्षेत्र से जुड़े कारीगर मेले में अपने उत्पाद बेचने में कामयाब रहेंगे. इस वर्ष मेले में दुमका एवं चाईबासा के सिल्क विशेष तौर पर मेले का आकर्षण होंगे.

अन्य राज्यों से भी पहुंचेंगे स्टॉलधारक

देश के विभिन्न राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात,कश्मीर, उड़ीसा इत्यादि सभी राज्यों से विभिन्न ट्रेंड के उत्पाद मेले में स्टॉल लगाएंगे. इनके द्वारा मेले में स्टॉल लगाने से उत्पादों से संबंधित जानकारी भी झारखंड के कारीगर अन्य राज्यों के कारीगर से आदान-प्रदान कर सकेंगे. झारखंड के कारीगरों को नए-नए चीजों को सीखने का मौका भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि वातावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मेले में संपूर्ण व्यवस्था वातावरण अनुकूल की जाएगी. प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा इसके लिए मेले में कैंप भी लगाए जाएंगे. वातावरण संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है और सबों की सहभागिता से ही यह संभव हो सकेगा. जेसोवा वातावरण संरक्षण के लिए अवेयरनेस कैंप चला कर लोगों को जागरूक करने का पहल कर रही है।

बच्चों के लिए होंगे एडवेंचर गेम्स

जेसोवा की मीडिया प्रभारी श्रीमती ऋचा संचिता ने कहा कि इस वर्ष मेले में बच्चों के लिए एडवेंचर्स गेम्स आयोजित किया जा रहा है. ज्ञान आधारित एडवेंचर्स गेम से बच्चों के मनोरंजन के साथ-साथ अन्य आगंतुकों का भी मनोरंजन होगा.

सामाजिक विकास में जेसोवा निभा रही है अपनी भूमिका

श्रीमती ऋचा संचिता ने कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जेसोवा शुरुआत से ही तत्परता से कार्य कर रहा है.जेसोवा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को मदद किया जा रहा है. इस वर्ष मेले में झा-रखंड की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जेसेवा नई ऑडियोलॉजी के साथ आगे आ रही है.

सभी स्टॉल एवं हैंगर्स हो चुके हैं बुक

जेसोवा दिवाली मेला 2019 की तैयारी अंतिम चरण में है. सभी तैयारियां कर ली गई हैं. मेले में सभी स्टॉल्स एवं हैंगर्स बुक हो चुके हैं. मेले में पहुंचने वाले आगंतुकों के लिए एंट्री टिकट ₹10 रखी गई है.

मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

मेले के उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास करेंगे. जेसोवा द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया है और उन्होंने अपनी सहमति भी दी है.

दोंग और दसाइ नृत्य होंगे मेले का आकर्षण

मेले के शुभारंभ के दिन दोंग नृत्य द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी. उसी तरह मेले के समापन के दिन दसाइ नृत्य द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जाएगी. यह नृत्य पूर्ण रूप से पारंपारिक हैं. मेले में ट्राईबल फूड्स के कई स्टाल लगाए जा रहे हैं. इससे ट्राईबल फूड्स के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा.

संवाददाता सम्मेलन के अवसर पर श्रीमती सरिता पांडे, श्रीमती दिव्या त्रिपाठी, श्रीमती मिनी सिंह, श्रीमती अमिता खंडेलवाल, श्रीमती परिणीता सिंह, श्रीमती प्रीति कुमार, श्रीमती शीला मिश्रा , श्रीमती मनु झा, श्रीमती ऋचा संचिता, श्रीमती श्वेता शुक्ला, श्रीमती रेखा विद्यासागर, डॉ स्टेफी टेरेसा मुर्मू सहित अन्य उपस्थित थीं।

गाय की खरीदारी के साथ होगा बीमा

टाना भगत परिवारों को अपनी पसंद की नस्ल की निःशुल्क चार दुधारू गाय खरीदने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उन गायों को रखने के लिए 346 शेडों का निर्माण पूरा हो चुका है। सभी लाभुकों को गोपालन से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। टाना भगतों की मांग पर मुख्य सचिव ने बताया कि गाय की खरी-दारी के साथ ही बीमा की भी व्यवस्था है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी कारण से क्षति होने पर बीमा की राशि ससमय मिले, इसकी व्यवस्था वे सुनिश्चित करें। साथ ही 28 सितंबर से लगने वाले पशु मेला में जाकर खुद गायों की खरीदारी करने के लिए भी टाना भगतों को कहा।

बिहार: रेनवाटर हार्वेस्टिंग पर नए कानून से कितना होगा फायदा

बिहार सरकार बहुत जल्द ऐसा कानून लाने जा रही है, जिसके तहत निजी भवनों में रेनवाटर ह-ार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। हालांकि पुराने कानून में भी रेनवाटर हार्वेस्टिंग का ढांचा तैयार करने की बात कही गई है, लेकिन इस नए कानून में इसे अनिवार्य किया जाएगा।इस कानून में पटना नगर निगम के अंतर्गत निजी बिल्डिंगों में ये ढांचा तैयार करने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में पांच प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। ये पटना नगर निगम के सभी चार सर्किलों पाटलीपुत्र सर्किल, कंकड़बाग सर्किल, बांकीपुर सर्किल और पटना सर्किल में लागू किया जाएगा और बाद में अन्य नगर निगमों तक इसका विस्तार किया जाएगा।प्रॉपर्टी टैक्स में छूट को लेकर जानकारों का कहना है कि इससे लोग प्रोत्साहित होंगे, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कानून में रेनवाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किये जाने से कितना फर्क पड़ेगा, इस पर संदेह है। पटना नगर निगम के रिटायर्ड सिटी मैनेजर अमित कुमार सिन्हा ने अपना अनुभव स-ाझा करते हुए कहा कि इस तरह के नियम पहले भी थे, लेकिन लोगों में इसको लेकर उदासीनता थी। उस वक्त नाम मात्र की बिल्डिंगों में ये व्यवस्था थी, बाकी लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कानून में संशोधन कर रेनवाटर हार्वेस्टंग की व्यवस्था को अनिवार्य करने से मकान मालिकों की बाध्यता होगी कि वे जल संचयन का ढांचा तैयार करें। संशोधन को लेकर रिपोर्ट जल्द ही स्टेट कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि स-रकारी व निजी बिल्डिंगों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का ढांचा स्थापित करने को अनिवार्य करने की स्कीम बिहार सरकार के जल-जीवन-हरियाली अभियान का हिस्सा है।

जलवायू परिवर्तन से जंग

जलवायु परिवर्तन और भूमि विषय पर संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा जारी विशेष रिपोर्ट ने वैश्विक तापवृद्घि से लड़ाई में एक नया आयाम जोड़ा है। इसने जलवायु संकट को दूर रखने के लिए भूमि के उचित इस्तेमाल को एक प्रमुख पूर्व शर्त बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले जीवाश्म ईंधन से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने मात्र से वैश्विक ताप वृद्घि को औद्योगिक युग के पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रोका जा सकता है। पेरिस जलवायु समझौते के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी को इसी स्तर पर रोकना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम में आ रहे बदलाव की प्रवृत्ति को सीमित करने के लिए जमीन के इस्तेमाल में व्यवस्थित बदलाव करने होंगे। रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में सूखा, गहन बारिश, बाढ़ के कारण जमीन का क्षरण होता है। जमीन की प्रकृति में गिरावट जलवायु परिवर्तन को इसलिए बढ़ावा देती है क्योंकि इससे उसकी कार्बन डाइ ऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित होती है। रिपोर्ट के अनुसार मानवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 23 फीसदी हिस्सा जंगल काटने, खेती, पशु चराने तथा जमीन से संबंधित अन्य गतिविधियों के कारण हो रहा है। अगर खाद्य उत्पादन के पहले और बाद की गतिविधियों मसलन कच्चे माल और उत्पादन के परिवहन, ऊर्जा खपत और खाद्य प्रसंस्करण को भी ध्यान में रखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की हिस्सेदारी बढ़कर 37 फीसदी हो जाती है। इन हालात को बदलने के लिए वनों की कटाई रोककर नए वन लगाने होंगे और हरित क्षेत्र में इजाफा करना होगा। साथ ही जमीन को भविष्य में होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाना होगा। सामान्य तौर पर माना जाता है कि सामान्य कार्बन चक्र से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों में भूमि और समुद्र 50 फीसदी के जिम्मेदार है। इस स्तर को स्थिर रखने की जरूरत है, इस-ाके लिए नए वन लगाने की गति, वनों की कटाई से तेज करनी होगी।

जलवायु परिवर्तन पर देश की कार्य योजना में कई मोर्चों पर समांतर कार्य योजना के साथ काम करने की बात सोची गई है। इसमें एक अहम घटक है वनों के माध्यम से वातावरण की ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकना। इसका लक्ष्य है वनों का विस्तार करके सन 2032 तक 2.5 से 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन का अवशोषण करना। बहरहाल मौजूदा गति से देखें तो यह बहुत दूर की कौड़ी है। अतीत में भूमि और जल संरक्षण के लिए गए उपाय भी समय के साथ बेकार साबित हुए। एक स्थानीय एजेंसी के अनुमानों के मुताबिक देश के भौगोलिक रकबे में से करीब 30 फीसदी जमीन का स्तर बिगड़ा है। गैर कृषि भूमि, चारागाह और गांवों की जमीन बेरुखी से खराब हो रहे हैं। कृषि योग्य भूमि अतिशय सिंचाई, उर्वरकों के प्रयोग आदि से बिगड़ रही है। इन पर अंकुश लगाना होगा। जमीन का इस्तेमाल उसकी क्षमता के मुताबिक किया जाना चाहिए। आईपीसीसी की यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र की दो अहम मंत्रिस्तरीय बैठकें होने वाली हैं। पहली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टु द यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिसर्टिफिके शन (सीओपी14) जो अगले महीने दिल्ली में होगी। दूसरी बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (सीओपी 25) दिसंबर में चिली के सेंटियागो में होनी है। यह रिपोर्ट दोनों बैठकों को अहम जानकारी मुहैया कराएगी। रिपोर्ट के परेशान करने वाले नतीजे बताते हैं कि मिट्टी का क्षरण प्राकृतिक गति की तुलना में 100 गुना तेज गति से हो रहा है। उम्मीद है कि दुनिया के देश इसे ध्यान में रखकर अपनी जलवायु परिवर्तन की योजना पर काम करेंगे। नया लक्ष्य जमीन का क्षरण रोकने और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रोकने के कदम साथ उठाने का होना चाहिए। इसमें ढिलाई महंगी पड़ेगी।

सी.सी.एल. मुख्यालय में विश्वकर्मा पूजा धुमधाम से मनाया गया

सी.सी.एल., मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची के विभिन्न विभागों - चालक संघ, विद्युत यांत्रिकी, सुरक्षा, टीए, प्रणाली विभाग, इलेक्ट्रोनिक्स, विक्रय, गुणवत्ता एवं अन्य विभागों में देव-शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर परंपरागत रूप से तथा हर्ष एवं उल्लास के साथ पूजा अर्चना की गई।सी.सी.एल. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री गोपाल सिंह, निदेशक (कार्मिक) श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री भोला सिंह, निदेशक (वित्त) श्री एन.के. अग्रवाल सहित विभिन्-न विभागों के महाप्रबंधक तथा विभागाध्यक्ष ने मुख्यालय स्थित सभी पूजा पंडालों का भ्रमण कर प्रार्थना किया एवं भगवान विश्वकर्मा के दर्शन किये। सी.सी.एल. कर्मियों ने भोजनावकाश के दौरान घुम-घुम कर पंडाल में प्रतिमा का दर्शन किये तथा प्रसाद और भोग भी ग्रहण किये।अवसर विशेष पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री गोपाल सिंह ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि आज उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है और इस अवसर विशेष पर शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है।

लाइन तालाब से गंदगी हटाने की सरना समिति ने की मांग

रांची: लाइन टैंक रोड़ स्थित तथा रांची नगर निगम से सटे चडरी तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, स्थानीय लोगों के बार-बार कंप्लेन करने के बावजूद भी ना ही वार्ड पार्षद और ना ही रांची नगर निगम की नींद नहीं खुली। सुबह में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी इस गंदगी से परेशान रहते हैं, अभी हाल के दिनों में ही समिति के युवाओं ने चडरी तालाब के चारों और 300 पौधा रोपण किया है। सुबह टहलने वाले लोग समिति के सदस्यों के द्वारा किए गए कार्यों से खुश है पर जब उनकी नजर तालाब की ओर जाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं निगम की कार्यशैली निराश करती है। कुछ साल पहले यहां तालाब में लापरवाही से बहुत सारी मछलियां भी मर गयी थीं।इस तालाब के आस पास के जगह को सालों भर साफ रखा रखा जाए ताकि लोग साफ-सुथरे माहौल पर टहल सकें।।

केवल छठ पूजा के समय ही साफ किया जाता है पर सालों भर इसकी स्थिति ऐसी बनी रहती है।

रवि मुंडा :महासचिव चडरी सरना समिति

कभी जल संसाधनों से समृद्ध थी राजधानी दिल्ली

अरविन्द यादव

अर्द्ध चंद्राकार आकृति और सूर्य मंदिर से लगे तालाब सूरजकंड में पत्थरों की सीढ़ियां और बांध थे। यह तालाब अरावली की पहाड़ियों में हुई बरसात का पानी जमा करता था. पानी के पंपों, बिजली और पानी साफ करने वाले रसायन क्लोरिन के भी बनने के काफी पहले से दिल्ली एक शहर रहा है। 11वीं सदी के बाद से तो यहां एक न एक शासक वंशों की राजधानी रहने के साथ ही यह बहुत समृद्ध और आबाद शहर रहा। अन्य बड़े शहरों के विपरीत इसकी स्थिति भी बार-बार बदलती रही है। आज शहर यमुना के किनारे बसा है पर पहले ऐसा नहीं था।

तोमर वंश के अनंगपाल ने सन 1020 में जिस जगह दिल्ली बसाई थी, यह आज के सूरजकुंड के पास है और यह अब हरियाणा की सीमा में आता है। इस शहर का नाम सूर्य मंदिर और उससे लगे पत्थर की सीढ़ियों वाले अर्द्ध चंद्राकार तालाब के चलते सूरजकुंड पड़ा। यह तालाब अरावली पर्वत पर पड़ने वाली बारिश के पानी को सहेजने के लिए बना था। फिरोजशाह तुगलक ने इसकी सीढ़ियों और गलियारे की मरम्मत कराई और पत्थर जड़वा दिए। सूरजकुंड के पास ही अनंगपुर बांध है, जिसमें स्थानीय पत्थरों का उपयोग हुआ है। तंग दर्रे में पत्थर भरकर बांध बनाया गया था। इसके बाद कई दिल्लियां बसी हैं और सबकी सब अरावली पहाड़ी शृंखला की तराई में ही बसीं। इन सभी नगरों में जल संचय की विस्तृत व्यवस्था थी, जिससे नगरवासियों को अपनी रोजाना की जरूरतें पूरी करने के लिए कहीं जाना न पड़े।किला रायपिथौरा: दक्षिणी दिल्ली में सल्तनत वाले दौर के जल प्रबंधों के अवशेष भरे पड़े हैं। किला रायपिथौरा (महरौली सन 1052) सल्तनत काल की पहली राजधानी थी और यह यमुना से 18 किमी. दूरी पर थी। इस पहाड़ी इलाके के भूगोल और इसकी ऊंचाई के चलते यहां यमुना से नहर के माध्यम से पानी लाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिर्फ बरसात का पानी सहेज लेने का विकल्प ही था। इसीलिए सुल्तान अल्तुतमिश ने हौज-ए-सुल्तानी या हौज-ए-अल्तुतमिश नामक विशाल सरोवर बनवाया। बाद में अलाउद्दीन खिल्जी और फिरोजशाह तुगलक ने इस तालाब की मरम्मत करवाई। फिरोजशाह तुगलक ने शासनकाल में शरारती लोगों ने तालाब को पानी पहुंचाने वाले जल मार्गों को बंद कर दिया था। सुल्तान ने नलियों को साफ करने और हौज को पानी से भरने का आदेश दिया। 200 मीटर लंबे और 125 मीटर चौड़े इस तालाब का पानी आज भी काकी साहब की दरगाह पर जाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तालाब में अब काफी गाद मिट्टी भर गई है और इसके जल ग्रहण क्षेत्र पर भवन निर्माताओं और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कब्जा जमा लिया है।तालाबों के साथ ही सुल्तानों और इनके अमीर-उनबों ने बावलियां (सीढ़ीदार कुएं) बनवाईं और उनकी देखरेख की। ये बावलियां निजी जागीर नहीं थीं और इसके सभी धर्मों और जातियों के लोग पानी ले सकते थे। गंधक की बावली सुल्तान अल्तुतमिश के समय बनी थी और पानी में गंधक की मात्रा होने के चलते इसका यह नाम पड़ गया। पत्थरों से बनी इस खूबसूरत बावली का पानी आज भी नहाने-धोने के काम आता है। इसके पास ही राजों की बावली, दरगाह काकी साहब की बावली, महावीर स्थल के पीछे स्थित गुफानुमा बावली जैसी अनेक बावलियों के भग्नावशेष मौजूद हैं। इस काल में शहर के अन्य हिस्सों में भी बावलियां बनीं। इसमें निजामुद्दीन बावली, फिरोजशाह कोटला स्थित बावली और वसंत विहार स्थित मुरादाबाद की पहाड़ की बावली प्रमुख है। ये सभी आज तक उपयोग में आ रही हैं। लेकिन उग्रसेन की बावली, पालम बावली और सुल्तानपुर बावली वगैरह सूख चुकी हैं और इसके सिर्फ ढांचे खड़े हैं।सिरी: 1296 में बसी दूसरी दिल्ली, सिरी में (सन 1303) अलाउद्दीन खिल्जी ने एक विशाल जलाशय का निर्माण कराया। इस जलाशय का निर्माण भी अरावली पहाड़ियों पर गिरने वाले बरसाती पानी को सहेजने के लिए ही किया गया था। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 24.29 हेक्टेयर का था। इसकी लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई भी 600 मीटर थी। इसका नाम अलाउद्दीन खिल्जी के नाम पर हौज-ए-अलाई- रखा गया, जो बाद में बदलकर हौजखास बन गया। जलाशय के बांध अभी भी दिखते हैं। इसके उत्तरी और पश्चिमी बांध पर फिरोजशाह तुगलक ने मदरसा बनवा दिया।तुगलकाबाद: महरौली और सिरी की आबादी बढ़ने से गियासुद्दीन तुगलक बसाना पड़ा। यह जगह यमुना के पास थी, पर सुल्तान ने बस्ती के लिए पहाड़ी जमीन को चुना क्योंकि इससे किलेबंदी में काफी आसानी हो गई। तुगलकाबाद किले में सात तालाबों और तीन विशालकाय बावलियों के भग्यावशेष हैं। कुओं की गिनती आसान नहीं है। पहाड़ी से पूरब की तरफ बह जाने वाले पानी की जरूरतें पूरी की गईं। महरौली के निकट स्थित हौज-ए-शम्शी के अतिरिक्त पानी को नौलावी नाले के माध्यम से तुगलकाबाद तक ले जाया जाता था। इस प्राकृतिक जल के ढलाव वाली प्रणाली के एक हिस्से को हाल में बड़ा और पक्का करके गंदे नाले का रूप दे दिया गया जो अब शहर की नालियों का गंदा पानी आगरा नहर में पहुंचता है।

फोटो न्यूज

प्लास्टिक प्लेट का त्याग किजिये, पत्ते से बने प्लेट उपयोग करें जो इकोफ्रेंडली भी हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहतर हैं। फोटो : सचिन सिन्हा के फेसबुक वाल से

रांची कॉलेज के पीछे हातमा बस्ती में है यह छूपी हुई धरोहर मंदिर

आरओ और वाटर प्यूरीफायर पर कितना भरोसा?

भारत में आपका स्वागत है, यहां की शुद्ध हवा में सांस लीजिए। गंगा जैसी पवित्र और साफ नदी में स्नान कीजिए, उसका पानी पिएं। दिल्ली स्थित यमुना में मछलियों को दाना डालिए, यमुना के साफ पानी का इस्तेमाल कीजिए। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषण मुक्त देशों में से एक है यहां आपका स्वागत है।

पहली चार लाइन पढ़ें और अब कल्पना से हकीकत में आ जाएं। भारत की हवा और पानी कितना साफ है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं। एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ एयर और वाटर प्यूरीफायर की बिक्री भी भारत में बहुत बढ़ रही है। इसमें प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनियों का तो फायदा है, लेकिन यकीन मानिए इसमें आम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। साथ ही, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है जो शायद हम समझ नहीं पा रहे। रोटी, कपड़ा और मकान जिसे जरूरत समझा जाता है उससे भी बड़ी जरूरत है हवा और पानी। सांस लिए बिना दो मिनट नहीं बिता सकते, भूखा रहकर इंसान तीन हफ्ते तक जीवित रह सकता है, लेकिन प्यासा रहकर वो 1 हफ्ता भी नहीं बिता सकता. ये वैज्ञानिक फैक्ट हैं, लेकिन शायद रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को अहम मानकर हम ये भूल गए हैं कि हवा और पानी कितना जरूरी है. साफ हवा और साफ पानी हर इंसान की जरूरत है, लेकिन इसका असर क्या हो रहा है? हमे मिल रहा है प्रदूषित पानी और प्रदूषित हवा। नहीं, माफ कीजिए Purified हवा और Purified पानी।

तो इसमें दिक्कत क्या है?

हेमा मालिनी आकर कहती हैं 'केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।' ये विज्ञापन बहुत सालों से चला आ रहा है। वाटर प्यूरिफायर को लेकर ऐसे ही कई एड्स मौजूद हैं. कम से कम 60 कंपनियां भारत में वाटर प्यूरिफायर की सेल करती हैं और इतनी ही एयर प्यूरिफायर के लिए भी होंगी।ऐसे में दीपिका का विज्ञापन आता है जिसमें वो बाहर सांस भी नहीं ले पा रही है। उन्हें घर में एयर प्यूरिफाई करने वाला पेंट चाहिए।दीपिका एयर प्यूरिफायर को लेकर इतनी सख्त हैं कि उन्हें तो एसी भी घर में एयर प्यूरिफायर वाला ही चाहिए। ऐसे ही कई विज्ञापन हमें बताते हैं कि शुद्ध हवा और पानी पर हमारा हक है और वो हमें सिर्फ Air Purifier या वाटर प्यूरीफायर से ही मिलेंगे। ये सही है कि शुद्ध हवा और पानी पर हमारा हक है, लेकिन वो सिर्फ इन मशीनों से ही मिलेंगे क्या? ये नाकामी है इंसानी दिमाग की कि अगर उसे 10 बार एक झूठ बोला जाए तो उसे ही सच माना जाता है. एक गूगल सर्च आपको बता देगी कि आखिर एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर का नुकसान क्या है? क्यों इनके कारण हम नई-नई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं? ये सही है कि दूषित हवा-पानी से भी कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, लेकिन सादे पानी और हवा में कई तरह के मिनरल भी होते हैं जो इंसान के लिए जरूरी होते हैं. पर हम मशीनों पर इतने निर्भर हो गए हैं कि ये भूल ही गए कि ये मिनरल कितने जरूरी हैं जिन्हें ये मशीनें हमसे छीन रही हैं। खुद ही सोचिए, आखिरी बार आपने नल का पानी कब पिया होगा?

RO की बिक्री और समस्याओं पर हो चुकी हैं कई रिसर्च Reverse Osmosis यानी RO एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को प्यूरिफाई किया जाता है ताकि उसमें से कीटाणु और सॉलिड पदार्थ निकाले जा सकें. लेकिन इस प्रोसेस में जरूरी मिनरल और नमक (Mineral Salt) पानी से निकल जाते हैं और हमें मिलता है मरा हुआ पानी. भारत की बात करें तो यहां Water purifier market 24% की दर से आगे बढ़ रहा है. अगले दो सालों में ये सेल 2.5 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी. ये तब है जब आगरा, जोधपुर, वाराणसी, उदयपुर जैसे कई शहरों में भी अब इसकी बिक्री बढ़ गई है. डील्ल३ जो भारत में 40% मार्केट पर कब्जा किए हुए है उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। जहां एक ओर ये सब कुछ वाटर प्यूरिफायर की बिक्री से जुड़ा हुआ है वहां इसकी समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं।

NGT की रिपोर्ट बताती है वाटर प्यूरिफायर की समस्याएं

National Green Tribunal यानी NGT ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की थी. ये इसलिए ताकि आरओ सिस्टम का अति में होने वाला इस्तेमाल कम हो सके. रिपोर्ट में साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि जहां भी पानी में सॉलिड (total dissolved solids (TDS)) की मात्रा 500mg प्रति लीटर से कम हो वहां पर आरओ सिस्टम का इस्तेमाल बैन हो जाना चाहिए. इसी के साथ, रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि सरकार लोगों को बिना मिनरल वाला पानी पीने के दुष्परिणामों के बारे में बताए।इस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि सरकार ऐसा प्रावधान बनाए कि जहां भी आरओ का पानी इस्तेमाल हो रहा है वहां पर 60 प्रतिशत से ज्यादा बर्बाद हुआ पानी वापस इस्तेमाल में लाया जाए. जैसा कि आपको पता है अगर 1 लीटर पानी वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल होता है और पीने लायक बनता है तो 1 लीटर ही वेस्ट भी होता है। इस रिपोर्ट में ये भी आया है कि 13 राज्यों के 98 जिलों में पानी में TDS की मात्रा ज्यादा है वहां प्यूरिफायर बहुत जरूरी है, लेकिन बाकी जगह अन्य तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या किसी सरकारी विज्ञापन में ये दिखाया गया कि इसके नुकसान क्या हैं या फिर क्या आपके इलाके का नल का पानी शुद्ध है? नहीं बिलकुल नहीं. ऐसे में क्या उम्मीद की जाए साफ पानी की. साफ पानी की जगह हम तो शायद सिर्फ समस्याएं ही ले रहे हैं।Air Purifier के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। पूरी दुनिया में करीब 50 लाख लोग हर साल सिर्फ हवा में प्रदूषण के कारण मर जाते हैं. इसमें कई लोगों को बीमारियां हो जाती हैं. अगर सिर्फ भारत की बात करें तो 12 लाख से ज्यादा मौतें हर साल वायु प्रदूषण के कारण होती हैं. चीन और भारत दोनों में ही लोग इसके कारण मारे जाते हैं. ढट2.5 पार्टिकल जो दिल्ली एनसीआर में दीवाली के समय रहता है वो कई लोगों की बीमारियों का कारण बनता है। इस सब खतरे के आगे हम एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं। कार में, ऑफिस में, घर में, लिफ्ट में, सभी जगह हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने का काम चल रहा है. पर क्या कभी ये सोचा जाता है कि इनका असर क्या होता है? सबसे पहले तो अगर एयर प्यूरिफायर सही मटेरियल से नहीं बना है तो ये उल्टा असर करेगा. दूसरे कई तरह के एयर प्यूरिफायर सिर्फ Ozone बनाते हैं. यानी वो Ozone के कण हवा में फेकते हैं. ऐसे प्यूरिफायर बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं और लोग बिना सोचे समझे उन्हें ले भी लेते हैं। प्यूरिफायर बनाने वाले कहते हैं कि ये सभी तरह के बैक्टीरिया और खराब बदबू को खत्म कर देता है, लेकिन सच तो ये है कि कम मात्रा में Ozone कुछ असर नहीं दिखाएगा। लेकिन इसका लेवल इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। US FDA ने Ozone का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में बंद कर दिया है। Ozone से सांस नली की समस्याएं हो सकती हैं और फेफड़ों में भी दिक्कत होती है।ऐसा माना जा रहा है कि भारत में एयर प्यूरिफायर सबसे ज्यादा तेज़ी से बिकने वाले होम अप्लायंस में से एक हैं। जो कुछ सालों पहले तक जरूरत नहीं समझे जाते थे वो अब 2.8-3 लाख के आंकड़े में हर साल बढ़ रहे हैं. यानी 30% की ग्रोथ. भले ही ये ज्यादा न समझा जाए, लेकिन कार के एयर प्यूरिफायर, ऑफिस और लिफ्ट, एसी और अन्य जगहों के एयर प्यूरिफायर मिला लें तो ये बेहद खतरनाक आंकड़ा बन जाएगा। एयर प्यूरिफायर अंदर की हवा तो फिर भी ठीक कर देते हैं, लेकिन बाहर और भी ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं. साथ ही एयर कंडीशनर की तरह ये भी माहौल को गर्म करते हैं.

भारत में जागरुकता की बहुत कमी है. गंगा को हम मां मानते हैं, लेकिन उसी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि एक ताजा रिपोर्ट ने बताया कि गंगा का पानी अब न तो नहाने, न इस्तेमाल करने योग्य बचा है. वाराणसी और कलकत्ता जैसे शहरों में तो गंगा बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है. ऐसा ही हाल हवा का है। भले ही हम कितने भी प्यूरिफायर इस्तेमाल कर लें, लेकिन पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के किसानों को सरकार ये नहीं समझा पा रही है कि वो पराली जलाना बंद कर दें. हर साल नवंबर-दिसंबर में दिल्ली गैस चेंबर बन जाता है, लेकिन हमें क्या हम तो एयर और वाटर प्यूरिफायर से खुश हैं। क्या लोगों को बीमारी, समस्या, प्रदूषण आदि के लिए जागरुक नहीं किया जा सकता है।

इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है।

आइए, पत्तलों की परंपरा को पुनर्जीवित करते हैं

पत्तल में भोजन के अद्भुत लाभ आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश मे 2000 से अधिक वनस्पतियों की पत्तियों से तैयार किये जाने वाले पत्तलों और उनसे होने वाले लाभों के विषय मे पारम्परिक चिकित्सकीय ज्ञान उपलब्ध है पर मुश्किल से पाँच प्रकार की वनस्पतियों का प्रयोग हम अपनी दिनचर्या मे करते है।आम तौर पर केले की पत्तियो मे खाना परोसा जाता है। प्राचीन ग्रंथों मे केले की पत्तियो पर परोसे गये भोजन को स्वास्थ्य के लिये लाभदायक बताया गया है। आजकल महंगे होटलों और रिसोर्ट मे भी केले की पत्तियों का यह प्रयोग होने लगा है। सुपारी के पत्तों से बनाई गई प्लेटों में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। जिसे प्लास्टिक, थर्माकोल के ऑप्शन में उतरा गया है क्योंकि थर्माकोल व प्लास्टिक के उपयोग से स्वास्थ्य को बहुत हानि भी पहुँच रही है । सुपारी के पत्तों का पत्तल केरल में बनाये जा रहे हैं और कीमत भी ज्यादा नही है , तक़रीबन 1.5, 2, रुपये साइज और क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग है।

पत्तलों से अन्य लाभ

1. सबसे पहले तो उसे धोना नहीं पड़ेगा, इसको हम सीधा मिटटी में दबा सकते है।
2. न पानी नष्ट होगा।
3. न ही कामवाली रखनी पड़ेगी, मासिक खर्च भी बचेगा।
4. न केमिकल उपयोग करने पड़ेंगे '
5. न केमिकल द्वारा शरीर को आंतरिक हानि पहुंचेगी।
6. अधिक से अधिक वृक्ष उगाये जायेंगे, जिससे कि अधिक आक्सीजन भी मिलेगी।
7. प्रदूषण भी घटेगा।
8. सबसे महत्वपूर्ण झूठे पत्तलों को एक जगह गाड़ने पर, खाद का निर्माण किया जा सकता है, एवं मिटटी की उपजाऊ क्षमता बढेगी।
9. पत्तल बनाने वालों को भी रोजगार प्राप्त होगा।
10. सबसे मुख्य लाभ, आप नदियों को दूषित होने से बहुत बड़े स्तर पर बचा सकते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो पानी आप बर्तन धोने में उपयोग कर रहे हो, वो केमिकल वाला पानी, पहले नाले में जायेगा, फिर आगे जाकर नदियों में ही छोड़ दिया जायेगा। जो जल प्रदूषण में आपको सहयोगी बनाता है। आजकल हर जगह भंडारे, विवाह शादियों पार्टियों में डिस्पोजल की जगह इन पत्तलों का प्रचलन करना चाहिए। आखिर इसके गुण को जानने के कारण ही पुराने समय में पत्तल पर भोजन परोसने की परंपरा रही होगी

- पलाश के पत्तल में भोजन करने से स्वर्ण के बर्तन में भोजन करने का पुण्य व आरोग्य मिलता है ।
- केले के पत्तल में भोजन करने से चांदी के बर्तन में भोजन करने का पुण्य व आरोग्य मिलता है।
- रक्त की अशुद्धता के कारण होने वाली बीमारियों के लिये पलाश से तैयार पत्तल को उपयोगी माना जाता है। पाचन तंत्र सम्बन्धी रोगों के लिये भी इस्का उपयोग होता है। आम तौर पर लाल फूलो वाले पलाश को हम जानते हैं पर सफेद फूलों वाला पलाश भी उपलब्ध है। इस दुर्लभ पलाश से तैयार पत्तल को बवासिर (पाइल्स) के रोगियों के लिये उपयोगी माना जाता है।
- जोडो के दर्द के लिये करंज की पत्तियों से तैयार पत्तल उपयोगी माना जाता है। पुरानी पत्तियों को नयी पत्तियों की तुलना मे अधिक उपयोगी माना जाता है।
- लकवा (पैरालिसिस) होने पर अमलतास की पत्तियों से तैयार पत्तलो को उपयोगी माना जाता है।

ऐसा सेव खाकर आप बीमार भी हो सकते हैं

An apple a day keep docters away वाली बात गलत साबित हो गयी।आप रोजाना खाने-पीने की चीजों में मिलावट की खबरें तो सुनते रहते होंगे। खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री राम विलास पासवान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।दरअसल, दक्षिणी दिल्ली के खान मार्केट में स्थित एक फलों की दुकान पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है क्योंकि राम विलास पासवान को दुकान से लाए गए सेबों में मोम की परत दिखी। जिसे कि सेबों को ज्यादा चमकदार दिखाने के लिए लगाया गया था। जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाया विभिन्न एजेंसियां कार्रवाई के मूड में आईं और उनके मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) को पत्र लिखकर उपभोक्ताओं को विष पदार्थ वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर ध्यान देने के लिए कहा है।पासवान ने कहा कि उन्होंने एक प्रतिष्ठित दुकान से सेबों को खरीदा था। उन्होंने कहा, 'जब मैं रशियन सलाद बनाने जा रहा था तो मैंने कुक से सेबों को धोने के लिए कहा। मैं इस बात को ध्यान में रखता हूं कि सभी चमकदार खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से धोया जाए। उसने मुझे बताया कि कई बार धोने के बावजूद सेब चमक रहे हैं। जब उसने चाकू से मोम की परत हटाई तो हमने पाया कि सेबों को चमकदार बनाने के लिए उसपर मोम की मोटी परत लगाई गई है। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।' मंत्री ने बताया कि इन आयातित सेबों की कीमत 420 रुपये प्रति किलोग्राम है।

क्यों नहीं संवर सकी हरमू नदी?

हरमू नदीः ठेके के काम से इसके किनारे तो संवर गये लेकिन इसका जल इतना प्रदूषित है कि आप हरमू नदी की ओर से नजरे हटा लेंगे। जबकी करोड़ो खर्च कर इसे थेम्स की तरह संवारने का प्लान था।

रांची : हरमू नदी को संवारने और प्रदूषण मुक्त करने पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसके उद्गम स्थल से लेकर इसके प्रवाह और लाख प्रयासों के बाद भी इसमें बहाये जा रहे नालों, सीवरों और कचड़े पर। करोड़ो खर्च हो गये, लेकिन नदी ज्यों की त्यों अपने उसी काले गंदे बदबूदार जल के साथ राजधानीवासियों को मुंह चिढा रही है। आखिर क्यों नहीं साफ हो सकी हरमू नदी। बताने वाले कहते हैं कि कभी हरमू नदी का जल कांच की तरह साफ हुआ करता था। तो आज इतने प्रयासों के बाद भी सिर्फ इसके किनारों को ही क्यों संवारा जा सका है? इसका पानी साफ क्यों नही हो रहा? जवाब स्पष्ट है सिर्फ सरकारी प्रयास से हरमू नदी कभी भी स्वच्छ सलीला नहीं हो सकती। जनता, मीडिया से लेकर, पर्यावरणविद इसके साफ न होने का उपहास तो उड़ा रहे हैं, पर इसके साफ न होने के कारण के निवारण पर कोई जोर नहीं है। हरमू नदी की पूरी लंबाई 11 किमी से भी कम है, लेकिन रांची के बीच से होकर गुजरने के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह स्वर्णरेखा की सहायक नदी है ऐसे में इसके अस्तित्व पर संकट स्वर्णरेखा नदी के लिये भी संकट है। अपने उदगम हाड़ीडूका से ही नदी पर संकट है। इटकी रोड में इसके उद्गम स्थल पर भी मानव निर्मित क्रिया कलापों से संकट है। नदी अतिक्रमण के कारण पहले से ही संकरी हो चुकी थी। इसके बाद संवारने के नाम पर इसे पार्क के किसी नहर या नाले की शक्ल में दोनों किनारों पर पत्थर लगा दिया गया। इससे इसकी गहराई में या प्रवाह में कोई लाभ नहीं होने वाला। इसका उद्गम लेटेराइट मिट्टी का है ।

इसमें पानी का मुख्य माध्यम बारिश है। बारिश कम होगी तो इसमें सालो भर पानी नहीं रहेगा। ऐसे में इसमें नाले और सीवर के गंदे पानी का ही प्रवाह दिखेगा जिसे रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब तक इसे संवारने में लगे जुडको और इगल इंफ्रा का काम उपहास का विषय बना हुआ है।

क्या करना होगा?

- जनभागीदारी : सरकार या इसे संवारने में लगी एजेंसी या नगर निगम लाख कुछ कर ले बगैर जन सहयोग के नदी साफ नहीं हो सकती।जब तक आमजन खुद अपनी जिम्मेवारी समझ कर इसे प्रदूषित होने से नहीं बचायेगा तब तक नदी साफ नहीं होगी।
- पर्यावरणविदों और भूवैज्ञानिकों की राय लेकर इसके उद्गम को दुरूस्त करने से लेकर इसके तल को दुरूस्त करने और जल प्रवाह की स्थिति बनाने की कोशिश करनी होगी।
- नदी में अतिक्रमण और बहाये जा रहे किसी भी नाले सिवरेज को फौरन सख्ती से रोकना होगा। सिर्फ नोटिस टांगने से कुछ नहीं होगा। आखिर नदी में कहीं से नाले बहाये जा रहे हैं और प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः मनोज कुमार शर्मा* (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN00962, email:greenrevolt2019@gmail.com. Ph. 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।